STUDY IQ PUBLICATIONS

प्रथम संस्करण

भारत की राजव्यवस्था

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए उपयोगी

संस्थापक की कलम से

प्रिय उम्मीदवारों,

हमारी भूगोल और अर्थव्यवस्था की किताब, 'फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफी', 'प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन जियोग्राफी' और 'इंडियन इकोनॉमी' को मिली शानदार प्रतिक्रिया के लिए हम आपको विनम्रतापूर्वक धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी किताबें लॉन्च होने के बाद से ही यूपीएससी सेगमेंट में अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिए बेस्ट सेलर लिस्ट में हैं।

हमारी यूपीएससी सीएसई की किताबों को मिली भारी सकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रेरणा लेते हुए, हम सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करने के अपने मिशन की दिशा में एक और छलांग लगा रहे हैं। स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन आपको हमारी पुस्तक ' भारत की राजव्यवस्था' के पहले संस्करण के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न है।

यह पुस्तक उन चिंताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिनका सामना छात्रों को सिविल सेवा की तैयारी के दौरान करना पड़ता है। छात्र अक्सर भ्रमित होते हैं कि क्या अध्ययन करना है, कितना अध्ययन करना है, किसी विषय के लिए आवश्यक ज्ञान की गहराई और आयोग द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। इन सबसे ऊपर, समेकित अध्ययन सामग्री की अनुपस्थिति और कई स्रोतों से सूचना हमारे छात्रों की तैयारी में बाधा डालती है।

यह पुस्तक इन समस्याओं से निपटने और छात्रों के ज्ञान के आधार में सुधार करने, उनकी तैयारी के दौरान उनके कीमती समय की बचत करने और उनके सामने आने वाली कई शैक्षणिक गलतफहमियों को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है।

इस पुस्तक की प्रमुख विशेषताएंः

- इस पुस्तक का उद्देश्य यूपीएससी की वर्तमान प्रवृत्तियों और पैटर्न के आधार पर आपकी तैयारी को केंद्रित और प्रासंगिक, पुनरीक्षण-अनुकूल और अप-टू-डेट बनाना है।
- यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की आवश्यकताएं इस पुस्तक का विशेष फोकस हैं।
- हमने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी बरती है कि सामग्री स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाली हो, ताकि छात्र अपने लाभ के लिए अवधारणाओं को सीख सकें और याद कर सकें।
- जहां भी आवश्यक हो, हमने छात्रों को मौलिक अवधारणाओं को समझने में मदद करने के लिए प्रासंगिक उदाहरण, ऐतिहासिक मामले और तालिकाओं को शामिल किया है।
- हमने प्रत्येक अध्याय के अंत में प्रासंगिक पिछले वर्ष के प्रश्नों को शामिल किया है ताकि छात्र प्रश्न की प्रवृत्ति को समझते हुए अपने ज्ञान का परीक्षण कर सकें।
- पूरी ईमानदारी और विनम्रता के साथ, स्टडी आईक्यू टीम आपकी तैयारी में सर्वश्रेष्ठ होने की कामना करती है, और हमें उम्मीद है कि यह पुस्तक आपकी यात्रा में आपकी मदद करेगी।

Happy Learning!!

Mohit Jindal, IIT-Bombay
Co-Founder, Study IQ Education,
Mentoring UPSC CSE Aspirants for past 7 years

विषय सूची

भाग 01: संविधान का निर्माण

अवधारणात्मक पृष्ठ.......2

1. संविधान का विकास.......5
   - 1.1 कंपनी का शासन (1773-1858).......6
   - 1.2 ताज का शासन (1857-1947).......10

2. संविधान का निर्माण.......16
   - 2.1 संविधान सभा की माँग.......16
   - 2.2 संविधान सभा का गठन.......17
   - 2.3 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा संविधान सभा में किए गए परिवर्तन.......18
   - 2.4 संविधान सभा के कार्य.......18
   - 2.5 संविधान सभा की समितियाँ.......19
   - 2.6 संविधान का अधिनियमन और प्रवर्तन.......20
   - 2.7 संविधान का प्रवर्तन.......20
   - 2.8 संविधान सभा की आलोचना.......21
   - 2.9 महत्वपूर्ण तथ्य.......22

3. संविधान की प्रमुख विशेषताएँ.......23
   - 3.1 भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ.......23
   - 3.2 भारतीय संविधान की आलोचना.......29
   - 3.3 भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना.......31

4. उद्देशिका (प्रस्तावना).......35
   - 4.1 उद्देशिका का महत्व.......35
   - 4.2 भारतीय संविधान की उद्देशिका.......35
   - 4.3 भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच अंतर.......37
   - 4.4 रेफरेंडम और जन-मत-संग्रह के बीच अंतर.......38
   - 4.5 संविधान अपनाने की तिथि.......40
   - 4.6 भारतीय संविधान में उद्देशिका का महत्व.......40

5. भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ 44
5.1 भारतीय संविधान के भाग 44
5.2 भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ 49

भाग 02: भारत एवं इसके नागरिक

अवधारणात्मक पृष्ठ 52

6. भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र 57
6.1 अनुच्छेद 1 57
6.2 अनुच्छेद 2 59
6.3 अनुच्छेद 2A 59
6.4 अनुच्छेद 3 59
6.5 अनुच्छेद 4 63
6.6 भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का संक्षिप्त इतिहास 63
6.7 समय के साथ कैसे हमारे राज्यों की प्रकृति और स्थिति में परिवर्तन हुआ? 64
6.8 स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन 65
6.9 1956 के बाद बनाए गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 66
6.10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना तिथि 69
6.11 पड़ोसियों के साथ भारत के क्षेत्रीय विवाद 70

7. नागरिकता 76
7.1 भारत में नागरिकता 76
7.2 प्रासंगिक अनुच्छेद 76
7.3 नागरिकता का अर्जन 78
7.4 नागरिकता की समाप्ति 79
7.5 एकल नागरिकता 80
7.6 विदेशी भारतीय नागरिक 81
7.7 अप्रवासी भारतीय (NRI) 83
7.8 भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) 83
7.9 विदेशियों को विनियमित करने के लिए कानून 85
7.10 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 85
7.11 एनपीआर क्या है? 86

भाग 03: अधिकार एवं कर्तव्य

8. राज्य के नीति निदेशक तत्त्व 90

8.1 निदेशक तत्त्वों की विशेषताएं 90

8.2 निदेशक तत्त्व न्यायालय में प्रवर्तनीय क्यों नहीं हैं? 90

8.3 निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण 92

8.4 भाग IV से बाहर के निर्देश 96

8.5 राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों का कार्यान्वयन 96

8.6 निदेशक सिद्धांतों की उपयोगिता 98

8.7 निदेशक सिद्धांतों की आलोचना 100

8.8 मौलिक अधिकार बनाम राज्य के नीति निदेशक तत्त्व 100

8.9 मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों के बीच संघर्ष 101

9. मौलिक कर्तव्य 104

9.1 स्वर्ण सिंह समिति 104

9.2 संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के पीछे आवश्यकता या तर्क 105

9.3 मौलिक कर्तव्यों की सूची 105

9.4 मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं 106

9.5 मौलिक कर्तव्यों के अनुप्रयोग 106

9.6 मौलिक कर्तव्यों का महत्व 107

9.7 मौलिक कर्तव्यों की आलोचना 108

9.8 वर्मा समिति की टिप्पणियां 108

9.9 मौलिक कर्तव्यों के संबंध में संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें 109

9.10 मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर 109

9.11 मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन 110

9.12 क्या हमें मौलिक कर्तव्यों को “लागू” करने के लिए विशिष्ट कानूनों की आवश्यकता है? 112

9.13 मौलिक अधिकारों, निदेशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के बीच संबंध 113

10. मौलिक अधिकार 115

10.1 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 115

10.2 अनुच्छेद 12 116

10.3 क्या राज्य में न्यायपालिका शामिल है? 118

10.4 अनुच्छेद 13 119

10.5 समानता का अधिकार 124

10.6 अनुच्छेद 14 124
10.7 अनुच्छेद 15 128
10.8 अनुच्छेद 16 131
10.9 अनुच्छेद 17 134
10.10 अनुच्छेद 18 135
10.11 स्वतंत्रता का अधिकार 136
10.12 अनुच्छेद 19 136
10.13 अनुच्छेद 20 145
10.14 अनुच्छेद 21 146
10.15 अनुच्छेद 21 (क) 154
10.16 अनुच्छेद 22 155
10.17 शोषण के विरुद्ध अधिकार 160
10.18 अनुच्छेद 23 160
10.19 अनुच्छेद 24 162
10.20 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 163
10.21 अनुच्छेद 25 163
10.22 अनुच्छेद 26 169
10.23 अनुच्छेद 27 170
10.24 अनुच्छेद 28 171
10.25 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 171
10.26 अनुच्छेद 29 172
10.27 अनुच्छेद 30 172
10.28 अनुच्छेद 32 176
10.29 अनुच्छेद 33 181
10.30 अनुच्छेद 34 182
10.31 अनुच्छेद 35 183
10.32 मूल अधिकारों के अपवाद 186
10.33 अनुच्छेद 31 क 186
10.34 अनुच्छेद 31 ख 187
10.35 अनुच्छेद 31 ग 187
10.36 मौलिक अधिकारों का महत्व 188
10.37 मौलिक अधिकारों की आलोचना 188

भाग 04: शासन प्रणाली

अवधारणात्मक पृष्ठ........ 191

11. संसदीय प्रणाली........ 196

11.1 अध्यक्षीय और संसदीय सरकार के बीच तुलना........ 196

11.2 सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताएं........ 196

11.3 अध्यक्षीय सरकार की विशेषता........ 197

12. संघीय प्रणाली........ 201

12.1 संघवाद का अर्थ........ 201

12.2 संघवाद के मॉडल........ 201

12.3 एकात्मक और संघीय प्रणाली के बीच अंतर........ 202

12.4 भारतीय संघवाद की विशेषताएं........ 202

12.5 भारतीय संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन........ 206

13. केंद्र-राज्य संबंध........ 208

13.1 विधायी संबंध........ 208

13.2 प्रशासनिक संबंध........ 211

13.3 वित्तीय संबंध........ 215

13.4 केंद्र-राज्य संबंधों में चुनौतियां........ 221

13.5 केंद्र-राज्य संबंधों पर सिफारिशें........ 222

13.6 आगे की राह........ 226

14. अंतर्राज्यीय संबंध........ 227

14.1 संवैधानिक प्रावधान........ 227

14.2 अनुच्छेद-262: अंतर्राज्यीय जल विवाद........ 228

14.3 अनुच्छेद 263: अंतर राज्यीय परिषद........ 230

14.4 अनुच्छेद-261: सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही........ 232

14.5 अनुच्छेद-301-307: अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य........ 232

14.6 अनुच्छेद- 301: व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता........ 233

14.7 आंचलिक परिषद (क्षेत्रीय परिषदें)........ 234

14.8 अंतर्राज्यीय संबंधों से जुड़े मुद्दे........ 235

भाग 05: कार्यपालिका

अवधारणात्मक पृष्ठ 238

15. राष्ट्रपति 241
- 15.1 नामांकन 242
- 15.2 राष्ट्रपति का निर्वाचन 242
- 15.3 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता 244
- 15.4 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 244
- 15.5 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें 244
- 15.6 कार्यकाल 245
- 15.7 राष्ट्रपति पर महाभियोग 245
- 15.8 रिक्तियां 246
- 15.9 राष्ट्रपति की शक्तियाँ 246

16. उपराष्ट्रपति 255
- 16.1 उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 255
- 16.2 अर्हताएं 255
- 16.3 नामांकन 256
- 16.4 उपराष्ट्रपति का चुनाव 256

17. प्रधानमंत्री 260
- 17.1 प्रधानमंत्री से संबंधित संवैधानिक उपबन्ध 260
- 17.2 प्रधानमंत्री की नियुक्ति 260
- 17.3 प्रधानमंत्री पदकी अर्हता 261
- 17.4 प्रधानमंत्री की शपथ या प्रतिज्ञान 261
- 17.5 प्रधानमंत्री का कार्यकाल 261
- 17.6 वेतन और भत्ते 261
- 17.7 रिक्ति 261
- 17.8 प्रधानमंत्री की शक्तियां 262
- 17.9 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संवैधानिक संबंध 264

18. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद 266

19. मंत्रिमंडल समितियाँ........ 273

19.1 मंत्रिमंडल समितियों का विकास........ 273

19.2 मंत्रिमंडल समितियों की विशेषताएं........ 273

19.3 मंत्रिमंडल समितियों के कार्य........ 273

19.4 मंत्रियों का समूह (जीओएम)........ 276

20. राज्यपाल........ 278

20.1 राज्यपाल से संबधित संवैधानिक प्रावधान........ 278

20.2 राज्यपाल की नियुक्ति........ 278

20.3 राज्यपाल की योग्यताएं:........ 279

20.4 राज्यपाल के पद की शर्तें........ 279

20.5 राज्यपाल के पद की पदावधि........ 280

20.6 राज्यपाल की शक्तियां और कार्य........ 281

20.7 राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की तुलना........ 283

20.8 राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की तुलना........ 284

20.9 राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्तियों की तुलना........ 285

20.10 राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति........ 286

20.11 राज्यपाल-राज्य संबंध- एक विश्लेषण........ 287

21. मुख्यमंत्री........ 292

21.1 मुख्यमंत्री से संबंधित संवैधानिक प्रावधान........ 292

21.2 मुख्यमंत्री की नियुक्ति........ 292

21.3 योग्यता........ 293

21.4 शपथ........ 293

21.5 मुख्यमंत्री का कार्यकाल........ 293

21.6 वेतन और भत्ते........ 293

21.7 पद रिक्ति........ 293

21.8 मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य........ 294

22. राज्य मंत्रीपरिषद........ 296

22.1 संवैधानिक प्रावधान........ 296

22.2 राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना........ 298

22.3 मंत्री बनने के लिये योग्यता 298
22.4 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 298
22.5 मंत्रियों की शपथ और वेतन 298
22.6 राज्य मंत्रिपरिषद की भूमिका और कार्य 299
22.7 मंत्रियों के उत्तरदायित्व 299
22.8 कैबिनेट (मंत्रिमंडल) 300

भाग 06: विधायिका

अवधारणात्मक पृष्ठ 302

23. संसद 304

23.1 भारतीय संसद 304
23.2 प्रासंगिक अनुच्छेद 305
23.3 संसद के अंग 307
23.4 संसद की सदस्यता 315
23.5 संसद के सदनों के कामकाज का संचालन 318
23.6 वेतन और भत्ते 319
23.7 संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा 319
23.8 संसद के अधिकारी 324
23.9 संसद का सचिवालय 330
23.10 संसद में नेता 331
23.11 संसद के सत्र 332
23.12 सदस्य सदनों में अपना वोट कैसे डालते हैं? 334
23.13 संसद में भाषा 336
23.14 लेमडक सत्र 336

24. संसदीय कार्यप्रणाली 337

24.1 संसदीय कार्यवाही 337
24.2 संसदीय कार्यवाहियों का संचालन 338
24.3 विधेयक 344
24.4 संसद की विधायी प्रक्रिया 349
24.5 बजट 352

24.6 निधि और अनुदान 357
24.7 संसद के कार्य 359
24.8 संसद के प्रदर्शन का मूल्यांकन 362
24.9 भारतीय संसद की शक्ति 362
24.10 संसदीय कार्य पद्धति की चुनौतियां 364
24.11 सुधार हेतु सुझाव 366
24.12 लोकसभा और राज्यसभा की तुलना 367
24.13 राज्यसभा: एक महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन 368
24.14 कुछ महत्त्वपूर्ण आंकड़े 370

25. संसदीय समूह, मंच और समितियां 376
25.1 संसदीय समितियां 376
25.2 संसदीय मंच 387
25.3 भारतीय संसदीय समूह 389
25.4 अंतर-संसदीय संघ 391

26. राज्य विधानमंडल 392
26.1 संवैधानिक प्रावधान पर एक नजर 392
26.2 द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य 394
26.3 विधान सभा 394
26.4 विधान परिषद 396
26.5 अयोग्यताएँ 397
26.6 विधानसभा सीटों की रिक्तियां 399
26.7 सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान 399
26.8 विधान सभा सदस्यों के वेतन और भत्ते 400
26.9 सभा के अध्यक्ष 400
26.10 विधानसभा के उपाध्यक्ष 401
26.11 राज्य विधायिका के सत्र 401
26.12 कोरम या गणपूर्ति 402
26.13 सभा में भाषा 402
26.14 राज्य विधायिका की कार्य प्रणाली 402
26.15 विधान सभा और विधान परिषद के बीच अंतर 405
26.16 राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार 406
26.17 विधान सभा और विधान परिषद की शक्तियों की तुलना 407

भाग 07: न्यायपालिका

27. उच्चतम न्यायालय..410
27.1 संवैधानिक प्रावधान (ब्वदेजपजनजपवदंस च्तवअपेपवदे)..411
27.2 संरचना/संगठन..412
27.3 उच्चतम न्यायालय कास्थान/आसन...412
27.4 मुख्य परीक्षा हेतु...412
27.5 क्षेत्रीय न्यायपीठ/पीठ 412
27.6 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति...413
27.7 मुख्य परीक्षा हेतु;..415
27.8 अर्हताएँ 416
27.9 शपथ या प्रतिज्ञान...416
27.10 वेतन और भत्ते...417
27.11 न्यायाधीशों का कार्यकाल 417
27.12 न्यायाधीशों को हटाना..417
27.13 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश...418
27.14 तदर्थ न्यायाधीश..418
27.15 सेवानिवृत्त न्यायाधीश...418
27.16 सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्तियाँ 419
27.17 सेवानिवृत्ति के बाद वकालत 419
27.18 मुख्य परीक्षा हेतु...419
27.19 न्यायालय की प्रक्रिया..420
27.20 उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता..421
27.21 क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ...422
27.22 न्यायालय की अवमानना 426
27.23 सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्तियाँ...428
27.24 उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग).......................429
27.25 न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व...430
27.26 भारतीय न्यायालयों में लम्बित मामलें...431
27.27 न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी 433
27.28 मृत्यु दंड...435
27.29 स्वतंत्र भारत में प्रमुख मामले 439
27.30 निष्कर्ष 442

28. न्यायिक समीक्षा ... 446
28.1 न्यायिक समीक्षा का अर्थ ... 446
28.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ... 446
28.3 संवैधानिक प्रावधान ... 446
28.4 भारतीय संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत ... 447
28.5 संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में न्यायिक समीक्षा की तुलना ... 448
28.6 कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले आधार ... 449
28.7 न्यायिक समीक्षा के उदाहरण ... 449
28.8 न्यायिक समीक्षा का महत्त्वपूर्ण विश्लेषण ... 455
28.9 निष्कर्ष ... 455

29. न्यायिक सक्रियता ... 457
29.1 अर्थ ... 457
29.2 भारत में न्यायिक सक्रियता का विकास ... 457
29.3 न्यायिक सक्रियता के कारण ... 460
29.4 भारत में न्यायिक सक्रियता की अभिव्यक्ति ... 460
29.5 न्यायिक सक्रियता के ऐतिहासिक मामले ... 461
29.6 न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक ... 464
29.7 न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक ... 465
29.8 न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम ... 466
29.9 न्यायिक संयम के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ ... 467
29.10 न्यायिक सक्रियता का आलोचनात्मक विश्लेषण ... 467

30. जनहित याचिका ... 469
30.1 जनहित याचिका (पीआईएल) की परिभाषा ... 469
30.2 जनहित याचिका का विकास ... 469
30.3 भारत के लिए जनहित याचिका की आवश्यकता ... 470
30.4 जनहित याचिका की विशेषताएँ: ... 470
30.5 जनहित याचिका का दायरा (क्षेत्र) ... 470
30.6 जनहित याचिका के सिद्धांत ... 471
30.7 किसके खिलाफ पीआईएल दायर की जा सकती है? ... 472
30.8 जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया ... 473
30.9 जनहित याचिका स्वीकार करने के लिए दिशानिर्देश ... 473

30.10 भारत में जनहित याचिका: ऐतिहासिक निर्णय 474
30.11 भारत में जनहित याचिका (पीआईएल) का महत्त्व 475
30.12 भारत में जनहित याचिका (पीआईएल) की सीमाएँ/आलोचना 476

31. उच्च न्यायालय 477
31.1 प्रादेशिक क्षेत्राधिकार या क्षेत्रीय अधिकारिता : 477
31.2 संवैधानिक प्रावधान 477
31.3 नियुक्ति 478
31.4 योग्यता 478
31.5 शपथ या प्रतिज्ञान 478
31.6 वेतन और भत्ते 479
31.7 कार्यकाल 479
31.8 न्यायाधीशों को हटाना 479
31.9 न्यायाधीशों का स्थानांतरण 480
31.10 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 481
31.11 अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश 481
31.12 सेवानिवृत्त न्यायाधीश 481
31.13 उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता 481
31.14 न्यायिक क्षेत्र (क्षेत्राधिकार) और शक्तियाँ 482
31.15 न्यायाधिकरण के परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के क्षरण से संबंधित मुद्देः 486

32. न्यायाधिकरण/अधिकरण 488
32.1 न्यायाधिकरणों की आवश्यकता 488
32.2 एक न्यायाधिकरण, एक पारंपरिक न्यायालय में भिन्नता के बिंदु 488
32.3 संवैधानिक प्रावधान 489
32.4 प्रशासनिक न्यायाधिकरण 489
32.5 अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण 490
32.6 अनुच्छेद 323-A और अनुच्छेद 323-B की तुलना 491
32.7 न्यायाधिकरणों का युक्तिकरण 491

33. अधीनस्थ न्यायालय 493
33.1 संवैधानिक प्रावधान 493
33.2 न्यायाधीशों की नियुक्ति 493

33.3 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रस्ताव 494
33.4 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण 496
33.5 संरचना और अधिकार क्षेत्र 496
33.6 वैकल्पिक विवाद समाधान 497
33.7 ऑनलाइन विवाद समाधान 502
33.8 लोक अदालतें 504
33.9 ग्राम न्यायालय 506

34. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 509
34.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 509
34.2 भारत में अधिवक्ता 509
34.3 भारतीय विधिज्ञ परिषद् 510
34.4 राज्य विधिज्ञ परिषद् 511
34.5 भारतीय विधिज्ञ परिषद् का महत्त्वपूर्ण विश्लेषण 512

भाग 08: स्थानीय स्वसशासन एवं केंद्र शासित प्रदेश

अवधारणात्मक पृष्ठ.... 515

35. पंचायती राज संस्थान.... 518
35.1 पंचायती राज संस्थानों का विकास 518
35.2 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 523
35.3 राज्य चुनाव आयोग 526
35.4 ग्यारहवीं अनुसूची 527
35.5 वित्त 527
35.6 राज्य वित्त आयोग 528
35.7 अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधान 529
35.8 पेसा अधिनियम 529
35.9 मेन्स 531
35.10 पंचायती राज संस्थानों का महत्वः 531
35.11 पीआरआई को मजबूत करने के लिए सुधार और सुझावः 534
35.12 पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता संवर्धन के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहल 534

36. शहरी स्थानीय निकाय 538

36.1 शहरी निकायों का विकासक्रम 538

36.2 1992 का 74वां संशोधन अधिनियम 539

36.3 राज्य निर्वाचन आयोग 542

36.4 वित्त आयोग 542

36.5 जिला आयोजना समिति 543

36.6 महानगर आयोजना समिति 543

36.7 बारहवीं अनुसूचीः 544

36.8 शहरी सरकारों के प्रकार 544

36.9 नगर पालिका कार्मिकः 547

36.10 नगर पालिका राजस्व 548

36.11 स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषदः 549

36.12 शहरी स्थानीय निकायों के समक्ष चुनौतियां 549

36.13 सुधार और परामर्श 550

37. अनुसूचित क्षेत्र 551

37.1 अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन में उनकी आवश्यकता 551

37.2 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद 551

37.3 पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान 551

37.4 छठी अनुसूची क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान 552

37.5 पांचवीं और छठी अनुसूची के बीच अंतर 554

37.6 पांचवीं अनुसूची और अन्य विशेष श्रेणी के राज्यों से संबंधित मुद्दे 554

37.7 छठी अनुसूची क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे 554

37.8 आगे की राह 555

38. संघ शासित प्रदेश 557

38.1 केंद्र शासित प्रदेशों का विकास 557

38.2 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की आवश्यकता 558

38.3 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के बीच अंतर 558

38.4 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 559

38.5 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन 559

38.6 दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के लिए संवैधानिक प्रावधान 560

38.7 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मुद्दे 561

38.8 केंद्र शासित प्रदेशों के सुचारू प्रशासन के लिए सुधार 562
38.9 दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर बहस 563

भाग 09: संवैधानिक संशोधन एवं मूल ढाँचा

अवधारणात्मक पृष्ठ 566

39. मूलढांचा सिद्धांत की अवधारणा 568
39.1 भारत में बुनियादी ढांचे का विकास 568
39.2 मूल ढांचा सिद्धांत के तत्व 571
39.3 मूल ढांचा सिद्धांत का महत्वपूर्ण विश्लेषण 572

40. संविधान में संशोधन 574
40.1 संशोधन प्रक्रिया 574
40.2 संशोधन के प्रकार 575
40.3 संशोधन प्रक्रिया की आलोचना 576

41. आपातकालीन प्रावधान 578
41.1 भारतीय संविधान में आपात स्थितियों के प्रकार 578
41.2 राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के बीच अंतर 581
41.3 आपातकाल की आलोचना 584

भाग 10: संवैधानिक निकाय

अवधारणात्मक पृष्ठ 586

42. निर्वाचन आयोग 589
42.1 प्रासंगिक अनुच्छेद 589
42.2 निर्वाचन आयोग का क्रमिक विकास 590
42.3 संरचना एवं कार्यकाल 590
42.4 मुख्य निर्वाचन आयुक्त: समकक्षों में प्रथम 591
42.5 निर्वाचन संबंधी सुधारों पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट 593
42.6 भारत के निर्वाचन आयोग के प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक सुधार) 594

43. राज्य निर्वाचन आयोग 595
43.1 इतिहास 595

43.2 प्रासंगिक अनुच्छेद 596
43.3 राज्य निर्वाचन आयोग 596
43.4 राज्य निर्वाचन आयोग का महत्त्व 598
43.5 राज्य निर्वाचन आयोग के प्रभावी कार्य पद्धति के समक्ष चुनौतियाँ 599
43.6 राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए सुझाव 599
43.7 निष्कर्ष 600

44. लोक सेवा आयोग 601
44.1 प्रासंगिक अनुच्छेद 601
44.2 संघ लोक सेवा आयोग 601
44.3 राज्य लोक सेवा आयोग 606
44.4 संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग 608

45. वित्त आयोग 611
45.1 प्रासंगिक अनुच्छेद 611
45.2 संरचना और पदावधि 611
45.3 वित्त आयोग की कार्य पद्धति के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ 613
45.4 15वें वित्त आयोग को लेकर विवाद 613
45.5 वित्त आयोग का प्रदर्शन तथा राजकोषीय संघवाद 615
45.6 वित्त आयोग को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सुधार 616
45.7 निष्कर्ष 616

46. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 617
46.1 स्वतंत्रता से पूर्व तथा पश्चात में CAG के कार्यालय का क्रमिक विकास 617
46.2 प्रासंगिक अनुच्छेद 618
46.3 कर्तव्य और कार्य 619
46.4 अनुच्छेद 149: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ 619
46.5 CAG के प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) 620
46.6 CAG की स्वतंत्रता 621
46.7 CAG के अंतर्राष्ट्रीय संबंध 621
46.8 CAG और निगम 622
46.9 आलोचनात्मक विश्लेषण 622

47. वस्तु एवं सेवा कर परिषद ... 625

47.1 GST परिषद का क्रमिक विकास ... 625
47.2 GST परिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान- कालानुक्रम ... 625
47.3 GST परिषद का संघटन तथा संरचना ... 625
47.4 GST परिषद के कार्य ... 626
47.5 उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय तथा अद्यतन घटनाक्रम ... 627
47.6 GST परिषद के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ ... 627
47.7 सुझाए गए सुधार ... 628
47.8 राजकोषीय संघवाद पर GST का प्रभाव ... 628
47.9 अन्य चुनौतियाँ ... 629
47.10 भविष्य में उठाए जाने वालें कदम ... 629

48. भारत के महान्यायवादी ... 630

48.1 संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेद ... 630
48.2 भारत के महान्यायवादी पर प्रतिबन्ध ... 632
48.3 भारत के महान्यायवादी के पदकी प्रकृति ... 632
48.4 अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए महान्यायवादी की सहमति ... 633
48.5 भारत के महान्यायवादी की सूची ... 633
48.6 महान्यायवादी: संविधान के रक्षक या सरकार के प्रतिनिधि? ... 634
48.7 भारत के सॉलिसिटर और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ... 636
48.8 राज्य के महाधिवक्ता ... 636
48.9 महान्यायवादी और महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) के बीच अंतर ... 638

49. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ... 639

49.1 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का क्रमिक विकास ... 639
49.2 प्रासंगिक अनुच्छेद (Relevant Articles) ... 641
49.3 संरचना और पदावधि ... 642
49.4 आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis) ... 645

50. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ... 647

50.1 अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का क्रमिक विकास ... 647
50.2 प्रासंगिक अनुच्छेद ... 649
50.3 संरचना और पदावधि ... 651

50.4 आयोग के कार्य 651
50.5 आयोग की शक्तियाँ 652
50.6 आलोचनात्मक विश्लेषण 653

51. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 655
51.1 प्रासंगिक अनुच्छेद 655
51.2 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का क्रमिक विकास 655
51.3 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक निकाय के रूप में 660
51.4 नया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहले वाले आयोग से किस प्रकार भिन्न है? 662
51.5 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आलोचनात्मक विश्लेषण 662

52. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी 664
52.1 भाषाई अल्पसंख्यक 664
52.2 भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का कार्यालय 666
52.3 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी 667
52.4 52वीं रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु 668
52.5 आलोचनात्मक विश्लेषण 668
52.6 सुझाए गए सुधार 669

भाग 11: गैर-संवैधानिक निकाय

53. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 671
53.1 उद्देश्य 671
53.2 आयोग की संरचना 672
53.3 नियुक्ति 672
53.4 पदमुक्ति या त्यागपत्र 672
53.5 NHRC के कार्य और शक्तियाँ 673
53.6 चुनौतियाँ 673
53.7 आगे की राह 674
53.8 वर्तमान पहल 674
53.9 राज्य मानवाधिकार आयोग 675
53.10 अध्यक्ष, सदस्य और उनकी नियुक्ति 675
53.11 कार्य 675

54. केंद्रीय सूचना आयोग 677

54.1 संघटन और संरचना 677
54.2 शक्तियाँ और कार्य 678
54.3 राज्य सूचना आयोग 678
54.4 संघटन और संरचना 678
54.5 शक्तियाँ और कार्य 679
54.6 सुझाए गए सुधार 681
54.7 आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 और केन्द्रीय सूचना आयोग 682

55. नीति आयोग 684

55.1 स्थापना 684
55.2 नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह क्यों ली? 684
55.3 नीति आयोग: औचित्य या तर्काधार 685
55.4 नीति आयोग का संघटन 685
55.5 नीति आयोग के उद्देश्य 686
55.6 नीति आयोग की विशेषताएँ 688
55.7 नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत 688
55.8 अधीनस्थ, संलग्न और स्वायत्त निकाय 689
55.9 नीति आयोग के विशिष्ट शाखाएँ (विंग) 690
55.10 नीति आयोग की आलोचना 690
55.11 योजना आयोग 690
55.12 स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग की आवश्यकता क्यों थी? 691
55.13 कार्य 691
55.14 संघटन 691
55.15 आलोचनात्मक मूल्यांकन 692
55.16 राष्ट्रीय विकास परिषद् 693
55.17 एनडीसी में नीति आयोग के बाद के विकास 694
55.18 आलोचनात्मक मूल्यांकन 694
55.19 नीति आयोग और एनडीसी के बीच तुलना 694
55.20 सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद और नीति आयोग 694
55.21 सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की वर्तमान चुनौतियाँ 695
55.22 नीति आयोग की उपलब्धियाँ 696
55.23 नीति आयोग में सुधार हेतु सुझाव 696

56. केंद्रीय सतर्कता आयोग 699

56.1 केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) का ऐतिहासिक विकास 699

56.2 केन्द्रीय सतर्कता आयोग की संरचना और संघटन 699

56.3 केन्द्रीय सतर्कता आयोग की शक्तियाँ और कार्य 700

56.4 केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्वतंत्रता 701

56.5 चुनौतियाँ 702

56.6 सुझाए गए सुधार 702

57. लोकपाल और लोकायुक्त 704

57.1 भ्रष्टाचार क्या है? 704

57.2 लोकपाल (ओम्बुड्समैन) का विचार 704

57.3 भारत में भ्रष्टाचार 706

57.4 भारत में लोकपाल की कहानी 711

57.5 लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 712

57.6 लोकपाल 713

57.7 लोकायुक्त 716

57.8 लोकपाल और लोकायुक्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन 719

57.9 निष्कर्ष 721

58. राष्ट्रीय महिला आयोग 722

58.1 राष्ट्रीय महिला आयोग का विकास 722

58.2 महिलाओं से संबंधित अधिकार 723

58.3 राष्ट्रीय महिला आयोग संघटन (Composition) या संरचना 724

58.4 कार्यकाल 724

58.5 राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिदेश/कार्य 724

58.6 राष्ट्रीय महिला आयोग का आलोचनात्मक मूल्यांकन 726

58.7 राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की की गई पहल/उपलब्धियाँ 727

58.8 क्या राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए? 727

58.9 आगे की राह 728

59. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 729

59.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का विकास 729

59.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की संरचना 729

59.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का लक्ष्य 729
59.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य 730
59.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य 730
59.6 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति 730
59.7 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 731
59.8 संघटन 731
59.9 कार्य 731
59.10 राज्य कार्यकारी समिति 731
59.11 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 731
59.12 संघटन 731
59.13 कार्य 732

60. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 733
60.1 संघटन और संरचना 733
60.2 अधिनियम की महत्त्वपूर्ण धाराएँ 733
60.3 अधिनियम की पृष्ठभूमि 733
60.4 शिकायत निवारण (निस्तारण) की प्रक्रिया 734
60.5 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 735

61. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 736
61.1 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का विकास 736
61.2 प्रतिस्पर्धा अधिनियम (Competition Act), 2002 736
61.3 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उद्देश्य 737
61.4 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की संरचना 737
61.5 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्य 737
61.6 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सामने आने वाली चुनौतियाँ 738

62. भारत का विधि आयोग 739
62.1 भारतीय विधि आयोग का विकास 739
62.2 विधि आयोग की संरचना 740
62.3 विधि आयोग की भूमिका 740
62.4 विधि आयोग के कार्य 740
62.5 भारत का 22वां विधि आयोग 741

62.6 विधि आयोग की हालिया महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट 742

62.7 विधि आयोग की प्रमुख सिफारिशें (अनुशंसाएँ) 742

62.8 मुद्दे और चुनौतियाँ 743

62.9 विधि आयोग में सुधारों हेतु सुझाव 744

63. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 745

63.1 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की मुख्य विशेषताएँ 745

63.2 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का संघटन 745

63.3 सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) 746

63.4 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की संरचना 746

63.5 कार्य 746

64. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 748

64.1 संवैधानिक प्रावधान 748

64.2 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का विकास 748

64.3 संघटन और संरचना 749

64.4 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्य 749

64.5 मुफ्त कानूनी सेवाओं की प्रकृति 749

64.6 लाभार्थी 750

64.7 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ और उपाय 750

65. राष्ट्रीय हरित अधिकरण 752

65.1 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का विकास 752

65.2 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का संघटन और संरचना 753

65.3 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की शक्तियाँ 754

65.4 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्य 754

65.5 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का क्षेत्राधिकार 754

65.6 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का महत्त्व 755

65.7 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की उपलब्धियाँ 755

65.8 राष्ट्रीय हरित अधिकरणकी कार्य प्रणाली से जुड़ी चुनौतियाँ 755

65.9 सुधारों की आवश्यकता 757

66. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण 758

66.1 राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के पदाधिकारी 758

66.2 राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के गठन का समर्थन करने वाले कारण 758
66.3 राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के कार्य 759
66.4 राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का विजन (दृष्टिकोण) 759
66.5 राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का मिशन 759
66.6 राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का क्षेत्राधिकार 760
66.7 राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की जाँच प्रक्रिया 760
66.8 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 760

भाग 12: अन्य संवैधानिक आयाम

67. सहकारी समितियाँ/सहकारिता 763
67.1 सहकारिता की विशेषताएँ/अभिलक्षण 763
67.2 सहकारी समितियों के प्रकार 764
67.3 भारत में सहकारी आंदोलन 765
67.4 भारत में सहकारिता का नियमन 766
67.5 सहकारिता के गुण 769
67.6 भारत में सहकारिता के समक्ष चुनौतियाँ 769
67.7 अद्यतन सुधार 770
67.8 आगे की राह 771

68. राजभाषा 772
68.1 राजभाषा की स्थिति 772
68.2 संवैधानिक प्रावधान 772
68.3 संघ की भाषा 773
68.4 क्षेत्रीय भाषाएँ 774
68.5 न्यायपालिका की भाषा और विधि पाठ 775
68.6 विशेष निर्देश 775
68.7 राजभाषा अधिनियम और संसद की राजभाषा समिति 776
68.8 हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ 777
68.9 एक राष्ट्र - एक भाषा 778
68.10 हिंदी विरोधी आंदोलन 779
68.11 आगे की राह 779

69. सरकार के अधिकार और दायित्व 780
69.1 संवैधानिक प्रावधान 780
69.2 सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद 783
69.3 लोक अधिकारियों के विरुद्ध वाद 786

70. कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 788
70.1 प्रासंगिक अनुच्छेद 788
70.2 विशेष प्रावधानों का औचित्य 788
70.3 विशेष प्रावधानों का दायरा 789
70.4 कुछ निश्चित वर्ग कैसे निर्दिष्ट की जाती हैं? 789
70.5 विशेष प्रावधानों के घटक 791
70.6 इन प्रावधानों के प्रभाव 794

71. लोक सेवा 795
71.1 संवैधानिक प्रावधान 795
71.2 अखिल भारतीय सेवाएँ 796
71.3 केंद्रीय सेवाएँ 800
71.4 राज्य सेवाएँ 800
71.5 अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं की तुलना 802

भाग 13: राजनैतिक गतिशीलता

72. गठबंधन की सरकार 804
72.1 गठबंधन की विभिन्न परिभाषाएँ 804
72.2 गठबंधन सरकारें क्यों बनती हैं? 804
72.3 भारत में गठबंधन सरकार का विकास 805
72.4 गठबंधन सरकार की विशेषताएं 806
72.5 गठबंधन सरकार- एक विश्लेषण 807

73. राजनीतिक दल 808
73.1 राजनीतिक दलों का वर्गीकरण 808
73.2 दुनिया में दलों की प्रणालियां 810
73.3 भारतीय दल प्रणाली का विकास 811
73.4 भारतीय दल प्रणाली की विशेषताएं 811

73.5 राष्ट्रीय और राज्य दलों की मान्यता 812
73.6 भारत में राजनीतिक दलों के साथ समस्याएं....816

74. क्षेत्रीय राजनीतिक दल....818
74.1 क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं....818
74.2 भारत में क्षेत्रीय दलों का विकास....818
74.3 क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण:....818
74.4 क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण....819
74.5 राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका....819
74.6 क्षेत्रीय दलों से जुड़े मुद्दे....820

75. मतदान व्यवहार....821
75.1 मतदान व्यवहार का महत्व:....821
75.2 भारत में मतदान संबंधी व्यवहार और इसके निर्धारक....821
75.3 मीडिया की भूमिका....823
75.4 चुनावों में सोशल मीडिया की भूमिका- एक विश्लेषण....824

76. दबाव समूह....826
76.1 दबाव समूहों की विशेषताएं....826
76.2 भारत में दबाव समूहों के प्रकार....827
76.3 दबाव समूहों की तकनीक....830
76.4 दबाव समूहों के लाभ....830
76.5 दबाव समूहों से जुड़े मुद्दे....830

77. दल-बदल विरोधी कानून....832
77.1 दलबदल विरोधी कानून....832
77.2 दलबदल विरोधी कानून की मुख्य विशेषताएं....832
77.3 2003 का 91वां संशोधन अधिनियम....834
77.4 दलबदल विरोधी कानून का महत्व और आलोचना....834
77.5 दलबदल विरोधी पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय....835
77.6 दलबदल विरोधी कानून को मजबूत करना....836

78. विदेश नीति....837
78.1 विदेश नीति की भूमिका....837
78.2 विदेश नीति और राजनयिक संगठनों का इतिहास....837

78.3 भारत की विदेश नीति को आकार देने वाले कारक 837
78.4 भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत....838
78.5 एक सुसंगत विदेश नीति के लिए चुनौतियाँ....840
78.6 भारत की विदेश नीति के उद्देश्य 841
78.7 गुजराल सिद्धांत (1996)....841
78.8 भारत का परमाणु सिद्धांत 842
78.9 कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति (2012)....843
78.10 एक्ट ईस्ट नीति (2014)....844
78.11 एक्ट फार ईस्ट नीति 844
78.12 हाल के रुझान: 845

79. निर्वाचन प्रणाली.... 847
79.1 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का महत्व....847
79.2 भारत में चुनाव से संबंधित विवादास्पद मुद्दें....848
79.3 भारत में चुनावी सुधार....850
79.4 एक राष्ट्र एक चुनाव पर विश्लेषण....859
79.5 राजनीति के अपराधीकरण पर विश्लेषण 863

भाग 14: निर्वाचन

अवधारणात्मक पृष्ठ.... 869

80. चुनाव 874
80.1 चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान....874
80.2 भारत का चुनाव तंत्र (मशीनरी) 875
80.3 चुनाव प्रकिया....877
80.4 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)- एक विश्लेषण....880
80.5 पेपर बैलट (मतपत्र) व्यवस्था (सिस्टम) -एक विश्लेषण....882
80.6 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) ई-वोटिंग....885
80.7 अनिवार्य मतदान - एक विश्लेषण....886

81. चुनाव कानून.... 889
81.1 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्यों पेश किया गया था?....889
81.2 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 890

81.3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 890
81.4 परिसीमन 894
81.5 अन्य अधिनियम जो चुनाव से संबंधित हैं: 895
81.6 चुनाव से संबंधित नियम और आदेश 895
81.7 निर्वाचन कानून (संशोधन) विधेयक 2021 895

82. निर्वाचन प्रणाली 898

82.1 स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का महत्व 898
82.2 भारत में निर्वाचन से संबंधित मुद्दे 899
82.3 भारत में चुनावी सुधार 901
82.4 एक देश एक चुनाव पर विश्लेषण 910
82.5 राजनीति के अपराधीकरण पर विश्लेषण 913

प्रतिदर्श पेज

अवधारणात्मक पृष्ठ

संविधान क्या है?

एक संविधान एक राज्य के लिए नियमावली होती है। यह उन मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिनके द्वारा राज्यशासित होता है। यह राज्य की विभिन्न संस्थाओं का वर्णन करता है और उनके बीच संबंधों कोपरिभाषित करता है (उदाहरण के लिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य)। यह इन संस्थाओं की शक्ति की सीमा भी निर्धारित करता है और इसके नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है।

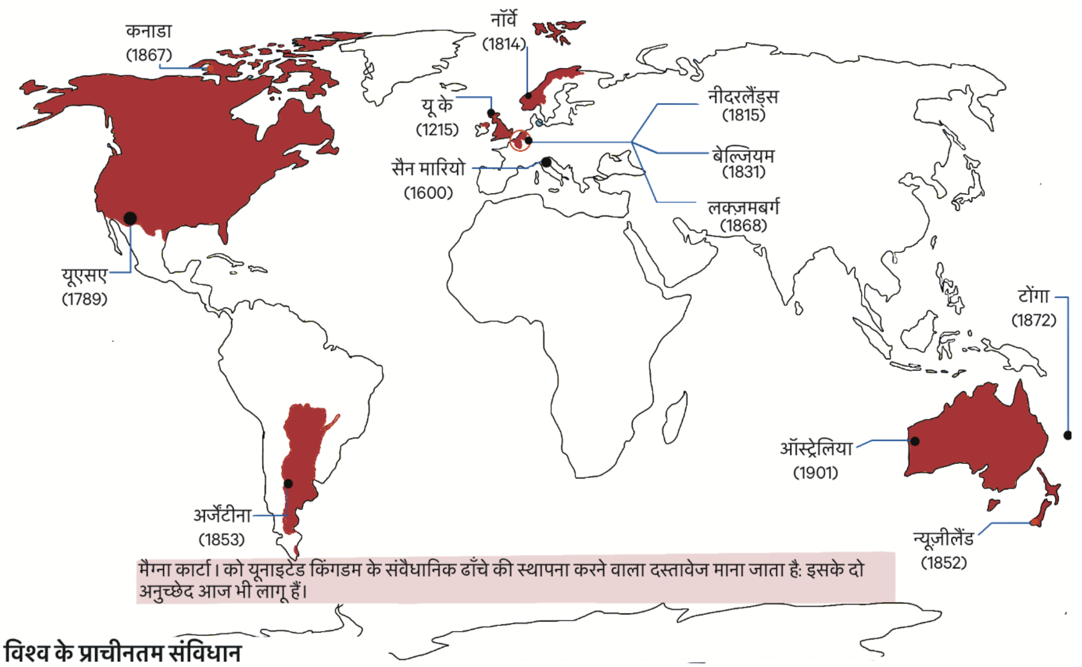

विश्व के प्राचीनतम संविधान

संविधान का उद्देश्य और कार्य

- **आधार भूत नियम:** एक संविधान बुनियादी नियमों का एक समूह प्रदान करता है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय की अनुमति देता है
- **सरकार का संविधान:** यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। यह तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी।
- **सरकार की शक्ति पर सीमाएँ:** सरकार अपने नागरिकों पर क्या आरोपित कर सकती है, इसकी कुछ सीमाएँ तय करती है। ये सीमाएँ इस अर्थ में मौलिक हैं कि सरकार कभी भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती है।
- **आकांक्षाएँ:** यह सरकार को एक समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक न्यायपूर्ण समाज के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने में सक्षम बनाता है।
- **मौलिक पहचान:** एक संविधान लोगों की मौलिक पहचान को व्यक्त करता है। इसका मतलब यह है कि एक सामूहिक इकाई के रूप में लोग मूल संविधान के माध्यम से ही अस्तित्व में आते हैं

विगत वर्ष के प्रश्न (यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? (2020)

(a) भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना।

(b) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाना।

(c) संघ की इकाइयों को राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाना।

(d) यह संघीय इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम है।

उत्तरः (d)

2. भारतीय राजव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन-सी एक अनिवार्य विशेषता है जो यह इंगित करती है कि यह स्वरूप में संघीय है? (2021)

(a) न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है।

(b) संघ विधानमंडल ने घटक इकाइयों के प्रतिनिधियों का चुनाव किया है।

(c) केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय दलों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं।

(d) न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य मौलिक अधिकार।

उत्तरः (a)

यूपीएससी मुख्य परीक्षा

प्र. संवैधानिक तंत्र अंतर-राज्यीय जल विवादों को हल करने में विफल रहे हैं। क्या यह विफलता संरचनात्मक या प्रक्रियागत अपर्याप्तता या दोनों के कारण है? चर्चा कीजिए। (2013)

प्र. यद्यपि हमारे संविधान में संघीय सिद्धांत प्रमुख है और यह सिद्धांत इसकी बुनियादी विशेषताओं में से एक है, यह भी उतना ही सच है कि भारतीय संविधान के तहत संघवाद एक मजबूत केंद्र के पक्ष में है, यह एक ऐसी विशेषता है जो मजबूत संघवाद की अवधारणा के खिलाफ है। चर्चा कीजिए। (2014)

प्र. हाल के वर्षों में सहकारी संघवाद की अवधारणा पर जोर दिया गया है। मौजूदा ढांचे में कमियों को उजागर कीजिए और सहकारी संघवाद किस सीमा तक कमियों को दूर करने में सक्षम होगा। (2015)

प्र. न्यायालयों द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में विवादास्पद मुद्दों के समाधान से 'संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत' और 'सामंजस्यपूर्ण निर्माण' का आविर्भाव हुआ है। स्पष्ट कीजिए। (10 अंक) (2019)

प्र. आपके विचार से भारत में संघ के स्वरूप को सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव ने कहाँ तक आकार दिया है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कुछ हालिया उदाहरण दीजिये। (उत्तर 150 शब्दों में) (2020)

© Study IQ Publications

- परमाणु ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों से निपटना।
- सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अन्य देशों के साथ समझौतों सहित आंतरिक या बाहरी सुरक्षा निहितार्थ वाले विदेशी मामलों से संबंधित नीतिगत मामलों से निपटना।

आवास के लिये मंत्रिमंडल समिति

रचना: इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। अन्य सदस्यों में विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

कार्य: मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- सरकारी आवास के बारी-बारी से आवंटन को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश या नियम और शर्तें निर्धारित करना।
- संसद सदस्यों को सामान्य पूल से आवास के आवंटन के प्रश्न पर विचार करना।
- अपात्र व्यक्तियों और संगठनों की विभिन्न श्रेणियों को सरकारी आवास के आवंटन और उनसे लिए जाने वाले किराए की दर का निर्णय करना।
- मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यालयों को दिल्ली के बाहर के स्थानों और दिल्ली में नए कार्यालयों के स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रस्तावों पर विचार करना।

निवेश और विकास के लियेमंत्रिमंडल समिति

रचना: इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। अन्य सदस्यों में विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

कार्य: मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- निवेश और विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार करना।
- नियमों और विनियमों के युक्तिकरण और सरलीकरण आदि सहित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए विभिन्न उपायों पर विचार करना।
- आवश्यक अनुमोदनों को तेजी से ट्रैक करने के उपायों और चल रही प्रमुख परियोजनाओं के साथ-साथ नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार करना।
- निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, पूंजी प्रवाह में तेजी, आदि के उद्देश्य से क्षेत्र-विशिष्ट सुधारों और अन्य उपायों पर विचार करना।
- निवेश और वृद्धि को बढ़ावा देने से संबंधित अन्य मामले पर विचार करना।

रोजगार और कौशल विकास के लिये मंत्रिमंडल समिति

रचना: इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। अन्य सदस्यों में विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

कार्य: मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य उपायों पर विचार करना।
- अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कौशल विकसित करने और कार्यबल की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उपायों पर विचार करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अंतराल की पहचान करना और उसे दूर करना।
- महिला कार्यबल पर विशेष जोर देते हुए कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उपायों पर विचार करना।
- मंत्रालयों/विभागों द्वारा रोजगार सृजन और कौशल विकास पहलों के शीघ्र कार्यान्वयन के उपायों पर विचार करना और इस संबंध में समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करना।

मंत्रियों का समूह (जीओएम)

ये आकस्मिक मुद्दों और महत्वपूर्ण समस्याओं पर मंत्रिमंडल को सिफारिशें देने के लिए गठित तदर्थ निकाय होते हैं। इनमें से कुछ मंत्री-समूहोंको मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार होता है जबकि अन्य मंत्रिमंडल को अनुशंसाएं भेजते हैं।

मंत्री-समूहकी संस्था मंत्रालयों के बीच समन्वय का एक व्यवहार्य और प्रभावी साधन हैं। संबंधित मंत्रालयों का

© Study IQ Publications

हैं। व्यक्तिगत हित कल्याण के उद्देश्य पर हावी होने लग सकते हैं और अन्य सदस्यों के लाभ को प्राथमिकता क्रम में पीछे छोड़ दिया जा सकता है यदि कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत लाभ को वरीयता दी जाती है।

- **विषम भौगोलिक पहुँच**
  - **वृद्धि में क्षेत्रीय असंतुलन:** उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा जैसे क्षेत्रों में सहकारी समितियाँ उतनी विकसित नहीं हैं जितनी कि महाराष्ट्र और गुजरात में हैं।
  - **सीमित क्षेत्र:** कई सहकारी समितियाँ कुछ सदस्यों तक ही सीमित हैं और उनके संचालन केवल एक या दो गाँवों तक सीमित व्याप्ति वाले हैं।
- **परिचालन चुनौतियाँ**
  - **सीमित संसाधन:** एक सहकारी समिति के संसाधनों में सीमित साधनों के साथ सदस्यों का पूँजी योगदान होता है। निवेश पर दिए जाने वाले लाभांश की कम दर भी सदस्यों से सदस्यता या अधिक पूँजी आकर्षित करने में एक निवारक के रूप में कार्य करती है।
  - **प्रबंधन में अक्षमता:** स्वैच्छिक आधार पर मानद सेवाओं की पेशकश करने वाले सदस्य आमतौर पर प्रबंधन कार्यों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए पेशेवर रूप से सुसज्जित नहीं होते हैं। साथ ही, ऐसी संस्थाएँ उच्च वेतन देने में असमर्थता के कारण विशेषज्ञ/प्रशिक्षित/कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करने में असमर्थ हैं।
  - **निष्पक्ष लेखापरीक्षा तंत्र का अभाव**
  - **विभिन्न स्तरों पर विद्यमान सहकारी समितियों के बीच समन्वय का अभाव**
- **कार्यात्मक कमजोरी:** आकारिकी मितव्ययता की अनुपस्थिति; कुशल कार्यबल की कमी; व्यावसायिकता का अभाव आदि।

अद्यतन सुधार (Recent reforms)

सहकारिता मंत्रालय का गठन (Formation of the Ministry of Cooperation)

- भारत में सहकारिता आंदोलन को कारगर बनाने के लिए 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था।
- यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढाँचा मुहैया कराएगा।
- इस कदम से पहले, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पास कृषि क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग था।
- मंत्रालय का आदेश
  - "सहकार से समृद्धि" विजन की प्राप्ति।
  - देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुँच को गहरा करना।
  - सहकार के क्षेत्र में सामान्य नीति और सभी क्षेत्रों में सहकार गतिविधियों का समन्वय।
  - सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत ढाँचे का निर्माण।
  - बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रशासन सहित एक राज्य तक सीमित न होने वाली सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन
  - सहकारी विभागों और संस्थानों के कर्मियों का प्रशिक्षण।

सहकारी समितियों के नियमन में परिवर्तन (Changes in regulation of cooperative societies)

- हाल ही में, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से बहु-राज्य सहकारी समितियों के नियमन में परिवर्तन किए गए थे।
- इसने एक बहु-राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के बदले पाँच साल तक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को जनहित में और जमाकर्ताओं की रक्षा करने का अधिकार दिया।